पूर्वोत्तर भारत में फर्जी समाचार: समस्याएँ और समाधान

- रीना कुमारी राय,
सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग,
अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज

सार: यह शोध लेख पूर्वोत्तर भारत में फर्जी समाचार प्रसार के जटिल परिदृश्य पर प्रकाश डालता है, इसके ऐतिहासिक, सामाजिक-राजनीतिक और तकनीकी आयामों की खोज करता है। क्षेत्र की विविध सांस्कृतिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, अध्ययन गलत सूचना को बढ़ावा देने वाले घरेलू और बाहरी कारकों की पहचान करता है और उनकी प्रेरणाओं और तकनीकों का आकलन करता है। समाज पर, विशेष रूप से सामाजिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता के संदर्भ में, वास्तविक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, अनुसंधान झूठी कहानियों के प्रसार को तेज करने में प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से सोशल मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालता है। लेख फर्जी खबरों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की वकालत करता है, जिसमें मीडिया साक्षरता कार्यक्रम, तथ्य-जाँच पहल और नियामक उपाय शामिल हैं। इन बहुआयामी गतिशीलता को समझकर, हितधारक पूर्वोत्तर भारत में गलत सूचना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी रणनीतियों की दिशा में काम कर सकते हैं, जो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

प्रस्तावना:

पूर्वोत्तर भारत, जो अपनी जटिल सांस्कृतिक पच्चीकारी और जटिल सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता की विशेषता वाला क्षेत्र है, एक गंभीर वैश्विक चुनौती - फर्जी खबरों के प्रसार - के चौराहे पर खड़ा है। इस अद्वितीय भौगोलिक विस्तार में ऐतिहासिक संघर्षों, जातीय विविधता और पहचान जटिलताओं का संगम गलत सूचना के तेजी से फैलने के लिए अतिसंवेदनशील वातावरण बनाता है। जैसे-जैसे डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियां आगे बढ़ रही हैं, फर्जी खबरों के निहितार्थ महज गलत सूचनाओं से आगे निकल रहे हैं, सामाजिक संरचनाओं में घुसपैठ कर रहे हैं, मौजूदा तनाव बढ़ा रहे हैं और सांप्रदायिक सद्भाव और राजनीतिक स्थिरता के मूल ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। यह शोध पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों के बहुमुखी आयामों को उजागर करने, इसकी ऐतिहासिक जड़ों की खोज करने, सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ की खोज करने और उस क्षेत्र पर प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है जो एक सूक्ष्म जगत और इसके द्वारा उत्पन्न व्यापक चुनौतियों का एक उदाहरण दोनों के रूप में कार्य करता है। ऐतिहासिक विरासतों, समकालीन सामाजिक-राजनीतिक गतिशीलता और तकनीकी प्रगति की जटिल परस्पर क्रिया को समझकर, इस अध्ययन का उद्देश्य फर्जी खबरों के प्रभाव को कम करने और क्षेत्र की

सामाजिक-सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है।

पूर्वोत्तर भारत, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्य शामिल हैं, एक समृद्ध ऐतिहासिक विविधता भरा हुआ है जो इसके समकालीन सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। क्षेत्र का ऐतिहासिक वर्णन विविध स्वदेशी संस्कृतियों, औपनिवेशिक छापों और स्वतंत्रता के बाद के संघर्षों की परस्पर क्रिया को दर्शाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से चले आ रहे इस क्षेत्र की ऐतिहासिक जटिलताएँ स्पष्ट हैं, क्योंकि बाहरी शासन संरचनाओं और मनमाने सीमा निर्धारण ने विशिष्ट जातीयताओं की अनदेखी की, जिससे स्थायी शिकायतों की नींव पड़ी। स्वतंत्रता के बाद के युग में स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करने वाले विद्रोही आंदोलनों का उदय हुआ, जिससे सामाजिक-राजनीतिक पेचीदगियों में परतें जुड़ गईं। पहचान, स्वायत्तता और संसाधन वितरण के लिए चल रहे संघर्ष केंद्र बिंदु बन गए हैं, जो क्षेत्र में राजनीति और सामाजिक संबंधों की गतिशीलता को आकार दे रहे हैं। ये ऐतिहासिक और समसामयिक चुनौतियाँ उस पृष्ठभूमि का निर्माण करती हैं जिसके विरुद्ध नकली समाचार फैलते हैं, मौजूदा दोष रेखाओं का लाभ उठाते हैं और पूर्वोत्तर भारत में सूचना प्रसार की जटिलता में योगदान करते हैं।

फर्जी खबरों की व्यापकता को समझने में यह ऐतिहासिक नजरिया महत्वपूर्ण हो जाता है। यह गलत सूचना के पीछे के उद्देश्यों, इसमें शामिल अभिनेताओं और उस क्षेत्र पर प्रभाव पर प्रकाश डालता है जहां ऐतिहासिक संघर्ष, उत्तर-औपनिवेशिक विरासत और पहचान के लिए समकालीन संघर्ष एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जहां गलत सूचना को रणनीतिक रूप से आगे के राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या मौजूदा तनाव को बढ़ाया जा सकता है। यह ऐतिहासिक और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों की जड़ों को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है और क्षेत्र में गलत सूचना के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने में इसकी जटिलताओं को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

घरेलू स्तर पर, राजनीति से प्रेरित व्यक्ति, स्थानीय मीडिया आउटलेट और क्षेत्र के भीतर हित समूह अक्सर भ्रामक जानकारी के जानबूझकर प्रसार में संलग्न होते हैं। आरोपित राजनीतिक माहौल और प्रचलित जातीय तनाव एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां गलत सूचना विशिष्ट आख्यानों को आगे बढ़ाने या निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक उपकरण बन जाती है। फर्जी खबरों के निर्माण और प्रसार के पीछे के उद्देश्यों और तरीकों को समझने के लिए इन घरेलू कारणों और सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ के बीच अंतरसंबंध को समझना आवश्यक है। बाह्य रूप से, विदेशी संस्थाओं और हित समूहों का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत में गलत सूचना के प्रसार में एक और परत का परिचय देता है। भू-राजनीतिक विचार और व्यापक दुष्प्रचार अभियान बाहरी तत्वों को क्षेत्र के विविध समुदायों के भीतर मौजूदा दोष रेखाओं का फायदा उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन बाहरी प्रभावों के पीछे की प्रेरणाएँ क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित करने के प्रयासों से लेकर सार्वजनिक धारणा में हेरफेर करने के उद्देश्य से अधिक वैश्विक

रणनीतियों तक हो सकती हैं। क्षेत्र को उसकी सीमाओं से परे उत्पन्न होने वाली गलत सूचना के प्रभाव से बचाने के लिए रणनीति विकसित करने में बाहरी ताकतों द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है।

डिजिटल युग में, गलत सूचना के माध्यम के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से अक्सर फर्जी खबरों का प्रसार तेज हो जाता है, जहां एल्गोरिदम और उपयोगकर्ता की सहभागिता झूठी कहानियों के प्रसार में योगदान करती है। इस प्रकार, अपराधियों की पहचान करने में न केवल मानवीय कारकों को समझना शामिल है, बल्कि भ्रामक जानकारी के तेजी से प्रसार को सुविधाजनक बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को भी पहचानना शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के लिए उन प्रेरणाओं, तरीकों और माध्यमों की गहन जांच की आवश्यकता है जिनके माध्यम से घरेलू और बाहरी दोनों तरह से गलत सूचना का प्रचार किया जाता है।

पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों के व्यापक प्रसार का क्षेत्र के सामाजिक ताने-बाने पर गहरा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रभाव समुदायों के भीतर और विविध जातीय समूहों के बीच विश्वास का क्षरण है। झूठी कहानियाँ अक्सर मौजूदा दोष रेखाओं का फायदा उठाती हैं, तनाव और अविश्वास को बढ़ाती हैं, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव कमजोर होता है जो क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। गलत सूचना वास्तविक दुनिया के परिणामों को भी भड़का सकती है, जिससे सामाजिक उथल-पुथल हो सकती है और कभी-कभी हिंसा भी हो सकती है। फर्जी खबरों से भड़के सांप्रदायिक झगड़े के उदाहरण देखे गए हैं, जो व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। सामाजिक प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र तक फैला हुआ है, जहां गलत सूचना के माध्यम से जनता की राय में हेरफेर चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकृति आ सकती है।

इसके अलावा, गलत जानकारी का प्रसार व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर सूचित निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी गलत सूचनाओं से लेकर विकृत राजनीतिक आख्यानों तक, सार्वजनिक धारणा और व्यवहार पर प्रभाव हानिकारक हो सकता है। सटीक जानकारी का यह क्षरण सामाजिक प्रगति को बाधित कर सकता है, रचनात्मक संवाद में बाधा डाल सकता है और पूर्वोत्तर भारतीय समुदायों के सामने मौजूदा चुनौतियों को बढ़ा सकता है। ऐसे में, समाज पर फर्जी खबरों के प्रभाव को संबोधित करना सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता और क्षेत्र की समग्र भलाई को बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाता है।

उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों के आगमन, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की सर्वव्यापकता ने पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल चैनलों के माध्यम से सूचना का तेजी से प्रसार गलत सूचना को भौगोलिक सीमाओं को तेजी से पार करने और कुछ ही क्षणों में विशाल दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति देता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, अपने एल्गोरिदम के साथ के उपयोगकर्ता जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अनजाने में इको चैंबर बनाते हैं जहां व्यक्तियों को ऐसी जानकारी से अवगत कराया जाता है जो उनकी मौजूदा मान्यताओं के साथ संरेखित होती है, जिससे झूठी कथाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलता

है। जिस आसानी से गलत सूचना ऑनलाइन बनाई, साझा और उपभोग की जा सकती है, वह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जोड़-तोड़ करने वाले कलाकार सनसनीखेज या पूरी तरह से गलत जानकारी प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया की वायरल प्रकृति का लाभ उठाते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के अंतर्निहित विश्वास का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा, जिस गति से जानकारी ऑनलाइन प्रसारित होती है, वह अक्सर तथ्य-जांच तंत्र से आगे निकल जाती है, जिससे भ्रामक सामग्री को उसकी सत्यता सत्यापित होने से पहले ही पकड़ मिल जाती है। प्रौद्योगिकी और फर्जी खबरों के अंतर्संबंध को संबोधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देना गलत सूचना के प्रभाव को कम करने के आवश्यक घटक हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों, नियामक निकायों और नागरिक समाज के बीच सहयोग पूर्वोत्तर भारत के डिजिटल परिदृश्य में फर्जी खबरों के प्रसार की पहचान करने और उसका मुकाबला करने के लिए उपकरणों और रणनीतियों के विकास में योगदान दे सकता है।

पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों की बहुमुखी चुनौती को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक व्यापक और सहयोगात्मक रणनीति की आवश्यकता है जो शैक्षिक, तकनीकी, नियामक और सामाजिक आयामों तक फैली हो। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत मीडिया साक्षरता कार्यक्रम लागू करना अत्यावश्यक है। इन कार्यक्रमों को व्यक्तियों को महत्वपूर्ण सोच कौशल से लैस करने, उन्हें विश्वसनीय सूचना स्रोतों को समझने, सामग्री की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने और असत्यापित जानकारी साझा करने के निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, तथ्य-जांच पहल फर्जी खबरों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारी और नागरिक समाज दोनों संस्थाओं द्वारा समर्थित स्वतंत्र तथ्य-जाँच संगठनों की स्थापना, सार्वजनिक तौर में प्रसारित होने वाली जानकारी का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन और सत्यापन कर सकती है। झूठे दावों का समय पर और पारदर्शी खुलासा न केवल एक सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है, बल्कि गलत सूचना के अनियंत्रित प्रसार के खिलाफ एक निवारक के रूप में भी कार्य करता है। तथ्य-जांचकर्ताओं का एक सुव्यवस्थित तंत्र झूठी कहानियों के तेजी से प्रसार का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है और सच्चाई का माहौल बनाने में योगदान दे सकता है। विनियामक उपायों की शुरूआत और कार्यान्वयन फर्जी खबरों से निपटने की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि ये उपाय स्वतंत्र भाषण के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं, गलत जानकारी के जानबूझकर प्रसार को संबोधित करने वाले कानून निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अनपेक्षित परिणामों को रोकने के लिए विनियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, और कानूनी ढांचे के विकास में नागरिक समाज संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल होने चाहिए। डिजिटल संचार के इस युग में प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों और नियामक अधिकारियों के बीच सहयोग अपरिहार्य है। सूचना प्रसार के लिए प्रमुख माध्यम होने के नाते, सोशल मीडिया कंपनियों को सक्रिय रूप से एल्गोरिदम लागू करने में संलग्न होना चाहिए जो झूठी जानकारी के प्रसार को पहचान और प्रतिबंधित कर सके।

इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में फर्जी खबरों के प्रसार से निपटने के लिए शिक्षा, प्रौद्योगिकी, विनियमन और सहयोग का एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। एक सूचित और आलोचनात्मक जनता को बढ़ावा देकर, तथ्य-जाँच तंत्र को मजबूत करके, विवेकपूर्ण नियामक उपायों को लागू करके और प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों को शामिल करके, क्षेत्र गलत सूचना के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और अधिक लचीला और सत्य-उन्मुख समाज के निर्माण की दिशा में काम कर सकता है।

निष्कर्ष:

पूर्वोत्तर भारत के अनूठे और विविध परिदृश्य में, फर्जी खबरों के खिलाफ लड़ाई एक अनुरूप और सहयोगी दृष्टिकोण की मांग करती है जो क्षेत्र की ऐतिहासिक, सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक बारीकियों का सम्मान करती है। जैसे ही यह व्यापक रणनीति आकार लेती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया साक्षरता की खेती सिर्फ एक शैक्षिक पहल नहीं है बल्कि इस क्षेत्र की विशेषता वाले सांप्रदायिक सद्भाव को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्तियों को सूचना के साथ गंभीर रूप से जुड़ने के लिए सशक्त बनाना एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में एक मूलभूत कदम है जो गलत सूचना की विभाजनकारी ताकतों के प्रति अवरोध हो। सरकारी और नागरिक समाज दोनों के सहयोग से संचालित तथ्य-जांच पहल, झूठी कहानियों के जटिल जाल को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो अक्सर ऐतिहासिक संघर्षों और जातीय तनावों का फायदा उठाते हैं। इन प्रयासों की पारदर्शिता और समयबद्धता सटीक जानकारी में विश्वास बहाल करने के लिए आवश्यक है, जो पूर्वोत्तर भारत के विविध समुदायों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

गलत सूचना पर अंकुश लगाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के बीच सही संतुलन बनाने के लिए नियामक उपाय आवश्यक होते हुए भी सावधानी के साथ किए जाने चाहिए। कानूनों के निर्माण और कार्यान्वयन को क्षेत्र की अनूठी चुनौतियों से अवगत कराया जाना चाहिए और विभिन्न हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकसित किया जाना चाहिए। डिजिटल युग में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के साथ सहयोग अपरिहार्य है। सोशल मीडिया कंपनियों को न केवल झूठी सूचनाओं की पहचान करने और उनके प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए एल्गोरिदम लागू करना चाहिए, बल्कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं को समझने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। उपयोगकर्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होता है कि व्यक्ति गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनें, जो पूर्वोत्तर भारत में सही सूचना पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में योगदान देता है।

निष्कर्षतः, चूंकि पूर्वोत्तर भारत फर्जी खबरों से निपटने के जटिल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षा, तथ्य-जांच, विनियमन और सहयोग को शामिल करने वाली एक समग्र रणनीति सर्वोपरि है। इस बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर, क्षेत्र न केवल गलत सूचना के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है, बल्कि एकता, विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव की नींव को भी मजबूत कर सकता है जो इसकी पहचान और प्रगति के लिए अभिन्न अंग हैं।

संदर्भ

1. सिंह, आलोक, (2021). "पूर्वोत्तर भारत: लोक और समाज.", सर्व भाषा ट्रस्ट, दिल्ली।
2. परमार, वीरेंद्र, (2018). "पूर्वोत्तर भारत: अतुल्य भारत", हिंदी बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
3. गोठी, ऋतु, (2017). "मीडिया प्रबंधन", लक्ष्य पब्लिकेशन, दिल्ली।
4. दुबे, दिवाकर, (2019). "सोशल मीडिया एक्टिविज्म: एक राजनीतिक हथियार", साहित्य भूमि, दिल्ली।
5. सिंह, कुमार, नागेन्द्र, (2020). "सोशल मीडिया और जनजातीय संस्कृति", स्वराज प्रकाशन, दिल्ली।
6. जाधव, रविंद्र, मोरे केशव, (2020). "आधुनिक मीडिया विमर्श", हिंदी बुक सेन्टर, नई दिल्ली।
7. मीना, लखन, राम,(2022). "मीडिया विमर्श: आधुनकि संदर्भ", कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली।